आरक्षित निर्णय

14.05.2019 को फैसला सुरक्षित

31.05.2019 को डिलीवरी की तिथि

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

रिट याचिका (आपराधिक) नं. 2019 का 28

सुश्री एक्स ..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ....प्रतिवादी

उपस्थित :- - सुश्री एक्स, याचिकाकर्ता, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित।

श्री जी. एस. संधू, सरकारी अधिवक्ता और श्री पी. एस. बोहरा, सरकार राज्य के लिए एक अतिरिक्त अधिवक्ता।

माननीय रवींद्र मैथानी, न्यायमूर्ति.

आपराधिक जनजाति अधिनियम, 1871 द्वारा राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण बनाम भारत संघ, (2014) 5 एस. सी. सी. 438 (जिद्वारा इसके पश्चात् 'नालसा का मामला' कहा गया है) के मामले में निर्णय की यात्रा अभी तक समाप्त नहीं हुई प्रतीत होती है।आपराधिक जनजाति अधिनियम कुछ जनजातियों और नपुंसकों के पंजीकरण, निगरानी और नियंत्रण के लिए अधिनियमित किया गया था।एनएएलएसए के मामले में व्यापक शब्द 'ट्रांसजेंडर' (टीजी) और उनके अधिकारों की व्याख्या, व्यापक चर्चा और समर्थन किया गया है।जिन लोगों का 'ब्रेन सेक्स' उनके 'जैविक लिंग' के अनुरूप नहीं था, उन्हें एनएएलएसए के मामले से स्वतंत्रता, स्वायत्तता, पहचान और गरिमा की अभिव्यक्ति मिली।एनएएलएसए का मामला, वास्तव में, कानूनी रूप से और साथ ही सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए सभी प्रकार के अपमान, पीड़ा, पीड़ा, आघात, संकट आदि को समाप्त करता है। जिसका सामना टीजी द्वारा किया जा सकता था। लेकिन, इस अदालत को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, जहां याचिकाकर्ता, एक ट्रांससेक्सुअल महिला, जिसकी लिंग पुनर्निर्धारण सर्जरी (जीआरएस) हुई है.

दावा करता है कि वह 'वह' है, लेकिन राज्य इसे मान्यता नहीं दे रहा है।याचिकाकर्ता अभी भी के. एस. के मामलों में NALSA के मामले में और उसके बाद के अधिकारों के बल पर राज्य की शक्ति के विरुद्ध अपनी आवाज उठा रही है। पुट्टास्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, (2017) 10 एससीसी 1 और नवतेज सिंह जौहर और अन्य, (2018) 10 एससीसी 1.

2. अग्रेतर बढ़ने से पहले, तथ्यों को एक नज़र में देखना उपयुक्त होगा।तत्काल मामले में, याचिकाकर्ता द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसे प्राथमिकी नं। भा.दं.सं. की धारा 377 और 385 के से 2018 की धारा 311। बलात्कार के भी आरोप हैं।याचिकाकर्ता का दावा है कि उसने अपनी पहचान 'वह' के रूप में बताई है।वह जी. आर. एस. से गुजरी है, इसलिए उसे एक महिला के रूप में माना जाना चाहिए।तत्काल याचिका राज्य सरकार को याचिकाकर्ता के साथ कानून के अनुसार महिला के रूप में व्यवहार करने और विचार करने का निर्देश देने के लिए दायर की गई है।

3. सुनवाई के दौरान, एक स्तर पर, उत्तराखंड सरकार के एक संयुक्त सचिव ने एक शपथ पत्र दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता को 'लिंग पहचान विकार' का पता चला है और कुछ चिकित्सा साक्ष्यों के आधार पर, भा.दं.सं. की धारा 376 और 377 के से जांच की गई थी, लेकिन बाद के चरण में, मामले के जांच अधिकारी ने अदालत में एक रिपोर्ट दायर की और याचिकाकर्ता के डीएनए को पढ़ने के आधार पर, जैविक रूप खंड घोषित किया कि याचिकाकर्ता 'वह' नहीं है, बल्कि 'वह' है।

इसके बाद, उत्तराखंड राज्य के गृह सचिव ने भी एक और शपथ पत्र दायर किया है और इसके पैराग्राफ 8 में, जैसा कि नीचे दिया गया हैः

"8. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तराखंड सरकार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ और अन्य में दिनांक 15.04.2014 के आदेश के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अक्षरशः पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में, उत्तराखंड सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अपने स्वयं के लिंग का निर्धारण करने के अधिकार की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है।इस प्रकार, याचिकाकर्ता को अपना लिंग निर्धारित करने का अधिकार है।

(महत्व दिया गया)

4. जांच पश्चात मामले में भा.दं.सं. की खंड 377 के से आरोप पत्र दायर किया गया है।

5. याचिकाकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुना, राज्य के लिए विद्वान सरकारी अधिवक्ता और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता और अभिलेखों का अवलोकन विद्वान

6. याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से तर्क देगा किः

(i) नालसा के मामले में फैसले को देखते हुए, उसने अपनी पहचान 'वह' के रूप में की है।

(ii) वह जी. आर. एस. से भी गुजरी थी और शल्य चिकित्सा करने वाले डॉक्टर ने उसे एक प्रमाण पत्र दिया है कि उसे "महिला" के रूप में संबोधित किया जा सकता है।

(iii) एक शपथ पत्र में, पैराग्राफ 8 में, जैसा कि यहां पहले उद्धृत किया गया है, यह भी स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता को अपने लिंग के आत्मनिर्णय का अधिकार है।

(iv) याचिकाकर्ता द्वारा दायर प्राथमिकी के आधार पर, आरोप पत्र भा.दं.सं. की धारा 376 के से दायर किया जाना चाहिए था। (v) याचिकाकर्ता द्वारा एक प्रश्न किए जाने पर, सामाजिक न्यायाधीश और अधिकारिता मंत्रालय ने भी पुष्टि की है कि तत्काल मामले जैखंड मामले में, याचिकाकर्ता के स्व-पहचान लिंग के अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए।पत्र का प्रासंगिक भाग, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष रखा गया है, इस प्रकार हैः

फाइल संख्या P.13011/3 (3)/2015-DP-III

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

"सेवा में

,

विषयः सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के से मांगी गई जानकारी।

मैडम,

कृपया आरटीआई अधिनियम के से जानकारी प्रस्तुत करने के लिए गृह मंत्रालय से हस्तांतरित अपने ऑनलाइन आवेदन दिनांक 26.03.2018 का संदर्भ लें।

2. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के निर्णय के पैराग्राफ 129 (2) के आलोक में पुलिस अधिकारियों द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के साथ महिला के रूप में व्यवहार के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि फैसले के पैरा 129 (2) के अनुसार "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों" को अपने स्वयं के लिंग का निर्धारण करने के अधिकार को बरकरार रखा गया था और केंद्र और राज्य सरकारों को उनके लिंग की पहचान जैसे पुरुष, महिला या

तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता देने का निर्देश दिया गया है।इसलिए, स्व-चिन्हित लिंग के अधिकार को बरकरार रखा जाता है।

3. यह अग्रेतर सूचित किया जाता है कि मंत्रालय ने लोकसभा में "ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण)" शीर्षक से एक विधेयक पेश किया है. विधेयक 2016 "ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए।उक्त विधेयक को लोकसभा द्वारा 17.12.2018 को पारित कर दिया गया है और यह विधेयक अब राज्यसभा में लंबित है।

4........

आपकी वफादार

(vi) राज्य सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को महिला के रूप में माना जाना चाहिए।

7. दूसरी ओर, राज्य की ओर से, विद्वान सरकारी अधिवक्ता और अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता तर्क देंगे किः

(i) यदि किसी व्यक्ति का "जैविक लिंग" व्यक्ति द्वारा निर्धारित लिंग के साथ भिन्न होता है, तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से घोषणा की आवश्यकता होगी।

(ii) यदि कोई व्यक्ति अपना लिंग निर्धारित करता है, तो इसे तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि संसद इस संबंध में कोई कानून नहीं बनाती।

(iii) यदि लिंग निर्धारण किसी व्यक्ति की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है, तो यह समाज में तबाही मचा देगा।

(iv) ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) विधेयक, 2018 अभी तक संसद द्वारा पारित नहीं किया गया है।

(v) जी. आर. एस. का संचालन करने वाले डॉक्टर द्वारा याचिकाकर्ता को जो भी प्रमाण पत्र दिया गया है, वह याचिकाकर्ता को महिला नहीं बना सकता है।

(vi) भा.दं.सं. खंड 375 का प्रावधान मात्र तभी आकर्षित होता है जब किसी महिला पर यौन हमला किया जाता है और इस मामले में यह तर्क दिया जाता है कि चूंकि याचिकाकर्ता का जैविक लिंग महिला नहीं है, इसलिए भा.दं.सं. खंड 375 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं।

8. इस न्यायालय को लिंग क्या है और लिंग क्या है, इस पर विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है।जन्म के समय सेक्स की अपनी विशेषता होती है।यह जैविक वर्गीकरण पर आधारित है, जबकि लिंग जैविक लिंग का सामाजिक संपर्क है।दोनों एक नहीं हैं, बल्कि परस्पर संबंधित हैं।लंबे समय से, लिंग की इस द्विआधारी धारणा ने टीजी को गरिमा या सम्मान के जीवन से वंचित कर दिया है। एन. ए. एल. एस. ए. के मामले में टी. जी. के सामने आने वाले आघात और पीड़ा पर विस्तार से चर्चा और विस्तार से बताया गया है।कॉर्बेट बनाम कॉर्बेट, 1970 (2) ऑल ई. आर. 33 के मामले में निर्धारित सिद्धांतों का संदर्भ दिया गया है।थोड़ा और विस्तार करने के लिए, यह ध्यान दें योग्य नहीं होगा कि कॉर्बेट के मामले में

क्या हुआ था।कॉर्बेट के मामले में, किसी व्यक्ति की यौन स्थिति का आकलन करने के लिए कुछ कारकों को वर्गीकृत किया गया था।इसे इस प्रकार देखा गयाः

> "मुझे अब यौन अंगों की शारीरिक और शारीरिक विसंगतियों से निपटना चाहिए, हालांकि मुझे लगता है कि साक्ष्य का यह हिस्सा मात्र वर्तमान मामले में मामूली महत्व का है।अन्य मामलों में, यह मुख्य महत्व का हो सकता है। सभी चिकित्सा गवाह प्रतिग्रहण करना करते हैं कि किसी व्यक्ति की यौन स्थिति का आकलन करने के लिए कम से कम चार मानदंड हैं।ये हैं-(i) क्रोमोसोमल कारक।(ii) गोनाडल कारक।(i.e., वृषण या अंडाशय की अनुपस्थिति में या अनुपस्थिति)।(iii) जननांग कारक (आंतरिक यौन अंगों सहित)।(iv) मनोवैज्ञानिक कारक।कुछ गवाह जोड़ेंगे-(v) हार्मोनल कारक या माध्यमिक यौन विशेषताएँ (जैसे बालों का वितरण, स्तन विकास, शरीर आदि जो शरीर में पुरुष और महिला सेक्स हार्मोन के बीच संतुलन को दर्शाते हैं)।और अदालत ने इस प्रकार निर्णय दियाः
>
> .फिर प्रश्न यह है कि.....विवाह के संदर्भ में 'महिला' शब्द का अर्थ है, क्योंकि मैं बड़े पैमाने पर प्रतिवादी के 'कानूनी लिंग' को निर्धारित करने के लिए चिंतित नहीं हूं।संबंध के अनिवार्य रूप से विषमलैंगिक चरित्र को ध्यान में रखते हुए, जिसे विवाह कहा जाता है, मानदंड, मेरे विचार में, जैविक होना चाहिए, यहां तक कि एक पुरुष में ट्रांससेक्सुअलिज्म की सबसे चरम डिग्री या सबसे गंभीर हार्मोनल असंतुलन जो पुरुष गुणसूत्र, पुरुष गोनाड्स और पुरुष जननांग वाले व्यक्ति में मौजूद हो सकता है, एक ऐसे व्यक्ति को पुनः उत्पन्न नहीं कर सकता है जो स्वाभाविक रूप से विवाह में एक महिला की आवश्यक भूमिका निभाने में सक्षम है।दूसरे शब्दों में, कानून को पहले स्थान पर, डॉक्टरों के मानदंडों में से पहले तीन को अपनाना चाहिए, i.e। गुणसूत्र, गोनाडल और जननांग परीक्षण, और, यदि तीनों समान हैं, तो तदनुसार विवाह के उद्देश्य के लिए लिंग निर्धारित करें, और किसी भी ऑपरेटिव हस्तक्षेप को अनदेखा करें।

9. कॉर्बेट के मामले का फैसला 'जैविक सेक्स' के आधार पर किया गया था न कि 'मनोवैज्ञानिक सेक्स' या 'ब्रेन सेक्स' के आधार पर।यह जैविक परीक्षण पर आधारित था।एन. ए. एल. एस. ए. के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न अधिकारिताओं के से मामलों का संदर्भ देते हुए निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित कियाः

> "37. ऊपर उल्लिखित निर्णय मुख्य रूप से ट्रांससेक्सुअल से संबंधित हैं, जो शारीरिक रूप से एक लिंग से संबंधित होने के बावजूद, आश्वस्त महसूस करते हैं कि वे दूसरे से संबंधित हैं, अपनी शारीरिक विशेषता को अनुकूलित करने के लिए चिकित्सा और शल्य चिकित्सा संचालन से गुजरकर एक अधिक एकीकृत स्पष्ट पहचान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जब हम ट्रांससेक्सुअल व्यक्तियों के अधिकारों की जांच करते हैं, जो एसआरएस से गुजर चुके हैं, तो लागू किया जाने वाला परीक्षण "जैविक परीक्षण" नहीं है, बल्कि "मनोवैज्ञानिक परीक्षण" है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक कारक और ट्रांससेक्सुअल की सोच को उस व्यक्ति के लिंग की द्विआधारी धारणा की तुलना में प्रधानता दी जानी चाहिए।शायद ही कभी लोगों को असुविधा, संकट और मनोवैज्ञानिक आघात का एहसास होता

है, जिससे वे गुजरते हैं और उनमें से कई "जेंडर डिस्फोरिया" से गुजरते हैं जिससे मानसिक विकार हो सकता है। हमारे समाज में इस समूह द्वारा सामना किया जाने वाला भेदभाव अकल्पनीय है और गुणसूत्र लिंग, जननांग, निर्धारित जन्म लिंग या निहित लिंग भूमिका के बावजूद उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।ट्रांसजेंडरों का अधिकार, शुद्ध और सरल, जैसे कि हिजड़े, हिजड़े आदि। तीसरी जाति के रूप में बने रहने के उनके अधिकार के साथ-साथ उनकी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अखंडता की भी जांच की जानी चाहिए।उन पहलुओं को अग्रेतर संबोधित करने से पहले, हम अन्य देशों में उनके अधिकारों को मान्यता देने वाले कुछ कानूनों का भी उल्लेख कर सकते हैं।

(महत्व दिया गया)

10. एनएएलएसए के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'जैविक परीक्षण' के सिद्धान्त को प्रतिग्रहण करना नहीं किया, बल्कि लिंग और लिंग के निर्धारण में व्यक्ति के मानस का पालन करना पसंद किया।इसे पैराग्राफ 81 में स्पष्ट रूप से रखा गया है, जो इस प्रकार हैः

"81. उपर्युक्त चर्चा के अनुच्छेद 14,15,16,19 और 21 से संकेत मिलता है कि वे हिजड़ों/ट्रांसजेंडरों को इसके दायरे से बाहर नहीं करते हैं, लेकिन भारतीय कानून समग्र रूप से किसी के जैविक लिंग के आधार पर पुरुष और महिला के द्विआधारी लिंग के प्रतिमान को मान्यता देता है।जैसा कि पहले से ही संकेत दिया गया है, हम "जैविक परीक्षण" के कॉर्बेट सिद्धान्त को प्रतिग्रहण करना नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम लिंग और लिंग निर्धारित करने में व्यक्ति के मानस का पालन करना पसंद करते हैं और "जैविक परीक्षण" के बजाय "मनोवैज्ञानिक परीक्षण" को प्राथमिकता देते हैं।लिंग की द्विआधारी धारणा भारतीय दंड संहिता में परिलक्षित होती है, उदाहरण के लिए, धारा 8,10, आदि। और विवाह, दत्तक ग्रहण, विवाह-विच्छेद, उत्तराधिकार और अन्य कल्याणकारी विधानों जैखंड कि NAREGA, 2005, आदि खंड संबंधित विधियों में भी। विभिन्न कानूनों में हिजड़ों/ट्रांसजेंडरों की पहचान की गैर-मान्यता उन्हें कानून के समान संरक्षण खंड वंचित करती है और उन्हें व्यापक भेदभाव का सामना करना पड़ता है।

(जोर दिया गया)

11. यहां ध्यान दें वाली बात यह है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केवल किसी व्यक्ति के लिंग निर्धारण में 'मनोवैज्ञानिक परीक्षण' पर विचार नहीं किया, बल्कि व्यक्ति के लिंग निर्धारण के लिए भी, 'जैविक परीक्षण' के बजाय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'साइक परीक्षण' को बरकरार रखा गया है।यदि कोई व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से अपने "जैविक लिंग" से अलग महसूस करता है और अपने मन के अनुसार खुद को निर्धारित करता है, तो एनएएलएसए के

मामले में फैसले को देखते हुए उसके लिंग का निर्धारण किया जाएगा।एनएएलएसए के मामले के पैराग्राफ 135 (2) में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टीजी व्यक्तियों को अपना लिंग निर्धारित करने का निरंकुश अधिकार दिया है।यह इस प्रकार हैः

> “135.2 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अपने स्वयं के लिंग का निर्धारण करने के अधिकार को भी बरकरार रखा गया है और केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी लिंग पहचान जैसे पुरुष, महिला या तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता देने का निर्देश दिया गया है।

(महत्व दिया गया)

12. यह सच है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) 2019 विधेयक बना रहा है और यह भी सच है कि ऐसा कोई अधिनियम नहीं है, जो टीजी व्यक्तियों के स्व-पहचाने गए लिंग या लिंग की पुष्टि करने वाली किसी भी घोषणा के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित करेगा, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या ऐसे किसी अधिनियम की अनुपस्थिति में में, नालसा के मामले में निर्देश लागू नहीं होंगे?नालसा के मामले का क्या प्रभाव है?

अपना निर्णय देते समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस स्थिति से अवगत था जब पैराग्राफ 53 में यह अभिनिर्धारित किया गया थाः

> “53.......दुर्भाग्य से हमारे पास......... इस देश में कोई कानून नहीं है जो ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों से संबंधित है।ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा करने वाले उपयुक्त कानून की अनुपस्थिति के कारण, उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का पालन करने की आवश्यकता है, जिसमें भारत एक पक्ष है और अन्य गैर-बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और सिद्धांतों को उचित सम्मान देने की आवश्यकता है।

और निर्णय के पैराग्राफ 60 में, माननीय न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

> "60. योगकर्ता सिद्धांतों सहित टीजी और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों पर पहले जिन सिद्धांतों पर चर्चा की गई है, जिन्हें हमने भारतीय संविधान के से गारंटीकृत विभिन्न मूल अधिकार के साथ असंगत नहीं पाया है, उन्हें मान्यता दी जानी चाहिए और उनका पालन किया जाना चाहिए, जिसका हमारे देश में पर्याप्त कानूनी और ऐतिहासिक औचित्य है।

(महत्व दिया गया)

13. ऐसा कोई अधिनियम नहीं है, जो टी. जी. के निर्धारित लिंग और लिंग की पुष्टि करने के लिए किसी भी प्रक्रिया को निर्धारित करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिंग और लिंग निर्धारित करने के लिए टीजी के अधिकार को बरकरार

रखा है।जब तक कोई कानून नहीं बनाया जाता, तब तक निश्चित रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून देश का कानून होगा।इसके पास, यदि अधिक नहीं तो, एक अधिनियम की समान शक्ति होगी जो विधायिका द्वारा बनाई जा सकती है।टीजी का अपने लिंग और लिंग को निर्धारित करने का अधिकार अब किसी भी कानून कानून की प्रतीक्षा नहीं कर सकता है।यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून है।यदि इस उद्देश्य के लिए किसी अधिनियम की प्रतीक्षा की जानी है तो यह टीजी की पीड़ा को अग्रेतर बढ़ा देगा।यह टीजी को जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के पूर्ण रूप से वंचित करने के अलावा और कुछ नहीं होगा और सबसे महत्वपूर्ण यह एनएएलएसए के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवज्ञा होगी।

14. इतना ही नहीं, K.S. के मामले में गोपनीयता के अधिकार के एक अन्य ऐतिहासिक निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा NALSA के मामले में निर्णय को बरकरार रखा गया मात्र। पुट्टास्वामी (ऊपर)।फैसले के पैराग्राफ 96 में, यह निम्नानुसार देखा गया थाः

> "96. एनएएलएसए अनुच्छेद 15 के भीतर लिंग पहचान के संरक्षण में निजता के अधिकार के आधार के लिए तर्क को इंगित करता है।अनुच्छेद 21 के साथ अनुच्छेद 15 का प्रतिच्छेदन व्यक्तिगत स्वायत्तता, गरिमा और पहचान की अभिव्यक्ति के रूप में निजता के संवैधानिक अधिकार का पता लगाता है।एनएएलएसए इंगित करता है कि निजता का अधिकार अनिवार्य रूप से मूल अधिकार के अध्याय में किसी एक प्रावधान के दायरे में नहीं आता है। अंतःविच्छेद अधिकार निजता के अधिकार को मान्यता देते हैं।हालांकि मुख्य रूप से, यह अनुच्छेद 21 के से जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी में है कि निजता का संवैधानिक अधिकार निहित है, यह अन्य अधिकारों में शामिल मूल्यों से समृद्ध है जो संविधान के भाग III में उल्लिखित हैं।

15. नवतेज सिंह जौहर (उपर्युक्त) के मामले में, नालसा के मामले में निर्णय पर चर्चा करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ 10 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी कीः

> "10. उपरोक्त निर्णय, जैसा कि स्पष्ट है, अविभाज्य "लिंग पहचान" पर ध्यान केंद्रित करता है और मानवाधिकारों और संवैधानिक रूप से गारंटीकृत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को गरिमा के साथ सही ढंग से जोड़ता है। यह ऐसे अधिकारों की न्यायिक मान्यता और संविधान के अनुच्छेद 21 के एक अटूट घटक पर जोर देता है और किसी भी भेदभाव की निंदा करता है क्योंकि यह हमारे संविधान के "न्यायशास्त्र" के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेगा।

16. अरुण कुमार और एक अन्य बनाम के मामले में। मद्रास उच्च न्यायालय अन्य बातों के साथ साथ मदुरै पीठ के रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक और अन्य, डब्ल्यूपी (एमडी) संख्या. 4125,2019 ने अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया है कि विधि के मार्ग के आलोक में, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 अन्य बातों के साथ साथ खंड 5 में होने वाली 'वधू' अभिव्यक्ति को इसके अर्थ में न मात्र एक महिला, अपितु एक ट्रांसवुमन को भी सम्मिलित करना होगा।

17. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि नालसा के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात याचिकाकर्ता के लिंग और लिंग निर्धारित करने के अधिकार का सम्मान और सम्मान किया जाना चाहिए।याचिकाकर्ता ने खुद को एक 'महिला' के रूप में पहचाना है, इसलिए, 'उसे' किसी भी प्राधिकरण से अग्रेतर की पुष्टि के बिना, सभी उद्देश्यों के लिए एक महिला के रूप में माना जाना चाहिए।

18. याचिकाकर्ता एक 'महिला' है।

19. तदनुसार रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

(रविन्द्र मैथानी, जज)

उज्जवल